जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 193 प्रभात बीकानेर, गुरूवार 5 फरवरी, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

लोकसभाध्यक्ष दुविधापूर्ण विडंबना में फंसे

उन्होंने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को तो पुस्तक के अंश उद्धृत करने दिए पर राहुल गांधी को पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की पुस्तक के अंश पढ़ने की इजाज़त नहीं दी

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- लोकसभाध्यक्ष की इस ''विवादपूर्ण'' व्यवस्था के कारण, कांग्रेस ने भारी हंगामा किया और प्र.मंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का उत्तर नहीं देने दिया।
- राहुल गांधी ने भाजपा सदस्यों की आपत्ति, कि पूर्व सेनाध्यक्ष नरवाणे की किताब अभी प्रकाशित हुई नहीं हुई उस अप्रकाशित पुस्तक के अंश कैसे लोकसभा में पढ़े जा सकते हैं, के जवाब में कहा, वे प्रकाशित पुस्तक की प्रति साथ लाए हैं, तथा उसकी प्रति प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे, जब प्र.मंत्री सदन में आएंगे।
- इस विवादित प्रकरण का अन्य पहलू यह भी है कि वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह व गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दावा किया था कि पूर्व सेनाध्यक्ष की पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, पर, राहुल गांधी ने कहा कि वे पुस्तक की प्रतिलिपि सदन में लाए हैं।
- तो क्या कांग्रेस, वरिष्ठ मंत्रीगणों के खिलाफ मिथ्यावचन का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का मामला बनाएगी।

नई दिल्ली, 4 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब नहीं दे सके क्योंकि लोकसभा में विपक्ष ने भारी हंगामा किया। राहुल गांधी को लद्दाख में चीन के हमले पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद यह हंगामा हुआ।

ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में भी भाषण नहीं देंगे और संभव है कि वह राज्यसभा में जवाब दें, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है।

हालांकि सूत्रों का कहना है कि सरकार आखिरी कोशिश कर रही है कि गतिरोध खत्म हो और विपक्ष से बातचीत शुरू हो सके। इसके लिए भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ बोले गए सभी आपत्तिजनक शब्द हटाए जा सकते हैं। वह किताबों से उद्धरण दे रहे थे और स्पीकर ने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की।

विपक्ष ने पूछा कि, क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के साथ व्यवहार के अलग-अलग मानदंड अपना रखे हैं।

इसी के विरोध में कांग्रेस सांसद स्पीकर के कक्ष में पहुंच गए और उनसे कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी को पत्रिका के लेख से उद्धरण देने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, जबकि निशिकांत दुबे को ऐसा करने दिया गया।

इस मुद्दे पर स्पीकर मुश्किल स्थिति में नज़र आ रहे हैं।

एक दिलचस्प घटनाक्रम में राहुल गांधी संसद में जनरल नरवणे की किताब की एक प्रति लेकर आए। उन्होंने मीडिया को वह किताब दिखाई और कहा कि जब प्रधानमंत्री सदन में आएंगे तो वह उन्हें इसकी एक प्रति देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें यकीन है कि नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आएंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल और मंत्री बिट्टू के बीच झड़प

- जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। आज सुबह संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हो गई। दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शन के दौरान गांधी ने पूर्व कांग्रेस नेता को ''गद्दार दोस्त'' कहा। इसके जवाब में बिट्टू ने गांधी को ''देश का दुश्मन'' बताया।

बिट्टू तीन बार सांसद रह चुके हैं और रेलवे राज्य मंत्री हैं। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा जॉइन कर ली थी।

- राहुल गांधी जब कांग्रेस सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर धरना दे रहे थे, तो वहां से गुज़र रहे मंत्री रवनीत बिट्टू, जो पहले कांग्रेस में थे, को उन्होंने ''गद्दार दोस्त'' कहा, बदले में बिट्टू ने उन्हें ''देश के दुश्मन'' करार दिया।

यह छोटी बहस उस समय हुई जब संसद के मकर द्वार के पास कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। जब बिट्टू पास से गुजरे तो गांधी ने कहा, '' देखो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को अपना ''राजनीतिक मंच'' बनाया

न्यायालय ममता जी की इस रणनीति का ''बेबस'' मूकदर्शक बनकर रह गया और ममता जी को निर्बाध रूप से पन्द्रह मिनट तक मुख्य चुनाव आयुक्त को भला-बुरा कहने का पूरा मौका मिला

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- इस दुःखद घटनाक्रम का दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पश्चिम बंगाल में फर्ज़ी मतदाता की रणनीति को तृणमूल कांग्रेस ने एक कला का रूप दे दिया है, निरंतर सुधार-संवार कर।
- 56 लाख से भी ज्यादा फर्ज़ी वोटर पाए गए थे, गत सूची पर गहराई से काम करने से। इसके अलावा गत सूची में बहुत से नाम उन व्यक्तियों के हैं, जो मृत हो चुके हैं तथा नियमित रूप से बांग्लादेश से, सीमा पार से, गैर कानूनी घुसपैठिए आकर चुनावों में मतदान करते रहे हैं।
- एसआईआर (वोटर सूची का शुद्धिकरण) 4 नवंबर 2025 को आरंभ हुआ था। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में परिवर्तन की अंतिम तारीख 19 जनवरी थी और फाइनल सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होनी है।

नई दिल्ली, 4 फरवरी। ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख, ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य जजों के सामने चल रही कानूनी सुनवाई को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय के खिलाफ एक राजनीतिक भाषण में बदल दिया और इसमें बड़ी जीत हासिल की।

ममता बनर्जी ने बेहतरीन तरीके से राजनीतिक चाल चली और कोर्ट की कार्यवाही को बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई में बदल दिया। बनर्जी ने राज्य में अपने समर्थकों से वादा किया था कि वह बंगाल में मतदाता सूची का संशोधन बिल्कुल नहीं होने देंगी।

अब जब मतदाता सूची का संशोधन (रोल रिविज़न) लगभग पूरा हो चुका था और प्रक्रिया समाप्त होने वाली थी, तब ममता को लगा कि उन्हें बड़ा झटका लगा है। पिछली मतदाता सूचियों से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भूमिगत ''चिकन नैक'' रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरु

चिकन नैक एक संकड़ा भू भाग है, जो देश के नॉर्थ ईस्ट भाग को शेष भारत से जोड़ता है

- श्रीनंद झा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

- 20-22 किलोमीटर चौड़ा, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे ही चिकन नैक कहते हैं, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और चीन की सीमा से मात्र 130 किलोमीटर दूर है।
- बांग्लादेश के चीन के करीब जाने व चीन की मदद से चिकन नैक हथियाने के दावों के मद्देनज़र भारतीय रेल्वे ने भूमिगत रेल्वे ट्रैक बिछाने का काम शुरु किया है, क्योंकि किसी भी संकट की स्थिति में भी अंडरग्राउण्ड ट्रैक बाधित नहीं होगा।

नई दिल्ली, 4 फरवरी 'चिकन नेक' की सुरक्षा से जुड़े 'शीर्ष प्राथमिकता' वाले प्रोजेक्ट के तहत 40 किलोमीटर लंबे भूमिगत रेल कॉरिडोर के निर्माण का काम जल्द ही तेज़ी से शुरू किया जाएगा, यह दावा नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के अधिकारियों ने किया है।

बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से घिरे तथा सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर-जिसे 'चिकन नेक' भी कहा जाता है-के माध्यम से ही पूर्वोत्तर राज्यों का शेष भारत से ज़मीनी संपर्क संभव है। भारत की सबसे कमजोर कड़ी कहे जाने वाले इस संकरे भू-भाग की चौड़ाई लगभग 20-22 किलोमीटर है और यह चीन की चुम्बी घाटी से मात्र 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

हाल के महीनों में बांग्लादेश के चीन के करीब जाने के बाद 'चिकन नेक' को लेकर कूटनीतिक तनाव बढ़ा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों ने भारत के पूर्वोत्तर भाग को अलग-थलग करने के उद्देश्य से चिकन नेक को जाम करने की खुली अपील की है, साथ ही कुछ उग्रवादी संगठनों ने इस कॉरिडोर को ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की अपनी परिकल्पना का हिस्सा बताया है।

इस खंड में भूमिगत रेल लाइन बनाकर भारत संभावित सुरक्षा खतरों से निपटना और सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मज़बूत करना चाहता है। एनएफआर के महाप्रबंधक चेतन श्रीवास्तव ने कहा कि यह रेल खंड पश्चिम बंगाल में टिन माइल हाट से रंगापानी स्टेशन तक चलेगा।

2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध के दौरान सैन्य योजनाकारों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बोत्सवाना से 8 चीते 28 को मध्यप्रदेश आयेंगे

भोपाल, 04 फरवरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से भेंट कर असम से जंगली भैंसा मध्यप्रदेश लाने की प्रक्रिया सहित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की।

- असम से जंगली भैंसे भी मध्यप्रदेश लाने की तैयारी चल रही है।

उन्होंने बताया कि 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते मध्यप्रदेश लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर केंद्रीय मंत्री यादव से आवश्यक व्यवस्थाओं एवं सहयोग पर भी विस्तार से चर्चा हुई है।

डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास, रिजर्व फॉरेस्ट के विस्तार और वन्य जीव संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीतों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल चुनावों पर देर रात भाजपा की बैठक

मंगलवार देर रात केन्द्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के घर हुई इस मीटिंग में पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद थे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- बैठक का फोकस मुख्य रूप से एसआईआर के संबंध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रणनीति का जवाब देने पर रहा, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी ने बेहद आक्रामक रूख अपना रखा है।
- मीटिंग में पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद शामिल हुए तथा पार्टी अध्यक्ष नबीन ने हरेक सांसद के साथ अलग-अलग मुलाकात कर फीडबैक लिया।
- सांसदों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में केन्द्रीय बजट को ''यंग इंडिया'' बजट के रूप में प्रचारित करें। इसके अलावा राज्य सरकार की विफलताओं पर आक्रामक रूख अपनाने और आंदोलन करने का निर्देश दिया गया, साथ ही कहा गया कि चुनाव होने तक आंदोलन जारी रहने चाहिए।

नई दिल्ली, 4 फरवरी। आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार देर रात पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर एक अहम बैठक दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री और भाजपा सांसद सुकांत मजूमदार के आवास पर हुई।

बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी मौजूद रहे। पश्चिम बंगाल से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसद और पार्टी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और सह-प्रभारी बिप्लब देब भी चर्चा में शामिल हुए।

यह बैठक पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसमें संगठनात्मक मजबूती, बूथ-स्तरीय योजना और समग्र चुनावी रोडमैप पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक का प्रमुख फोकस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर मुद्दे से निपटने की रणनीति पर था। यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने मतदाता सूची की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया।

करीब तीन घंटे चली इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने की। सभी सांसदों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर बजट 2026 के प्रमुख प्रावधानों को जनता के बीच स्पष्ट रूप से रखें। युवाओं तक पहुंच बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया और बजट 2026 को यंग इंडिया का बजट के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीति बनाई गई है।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए एक बड़ा और दीर्घकालिक प्लान तैयार किया है। इसी योजना के तहत नितिन नबीन ने सांसदों के साथ एक-एक कर व्यक्तिगत बैठकें कीं और उनसे सीधे फीडबैक लिया।

सांसदों को जमीनी स्तर पर राज्य सरकार की विफलताओं को आक्रामक तरीके से उजागर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्थानीय मुद्दों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ ज़ोन-वार आंदोलन शुरू करने को कहा गया है। रणनीति यह है कि इन आंदोलनों को विधानसभा चुनाव तक लगातार सक्रिय रखा जाए।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल चुनावों तक सांसदों से नियमित फीडबैक लिया जाता रहेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी की कट-ऑफ पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 4 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट-पीजी 2025-26 की परीक्षा के लिए कट-ऑफ पर्सेन्टाइल कम करने के राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड के निर्णय को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर बुधवार को नोटिस जारी किया।

- राष्ट्रीय चिकित्सा परीक्षा बोर्ड ने 13 जनवरी को कट-ऑफ पर्सेन्टाइल असामान्य रूप से कम कर दिया था।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने इस चुनौती पर गौर किया और निर्देश दिया कि मामले को छह फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

याचिका में परीक्षा बोर्ड की 13 जनवरी की उस अधिसूचना पर सवाल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा ममता बनर्जी ने

एक प्रशिक्षित एडवोकेट ममता बनर्जी पहली ऐसी मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मुकदमे की पैरवी की है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर इसकी अनुमति मांगी थी। ज्ञातव्य है कि ममता बनर्जी ने कहा था कि वे खुद एक वकील हैं और एसआईआर पर अपना केस खुद लड़ेंगी।
- ममता बनर्जी लम्बे समय से एसआईआर का विरोध कर रही हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव, 2025 की मतदाता सूची पर ही होने चाहिए।
- ममता बनर्जी ने एसआईआर में भारी विसंगतियों का आरोप लगाया और कहा कि कई महिलाओं के नाम इसलिए हटा दिए क्योंकि उन्होंने विवाह के बाद भारतीय परम्परा के तहत पति का सरनेम लगाना शुरु कर दिया था।
- सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बैंच ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि एसआईआर के संबंध में गणमान्य व्यक्तियों को नोटिस भेजते समय सावधानी बरते। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग ने पूर्व नौसेना एडमिरल अरूण प्रकाश, नोबल विजेता अमर्त्य सेन व क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी नोटिस भेजे हैं।

नई दिल्ली, 4 फरवरी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी स्वयं की। उन्होंने राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रीविज़न (एसआईआर) के खिलाफ दायर अपनी याचिका के समर्थन में दलीलें दीं।

ममता बनर्जी एक प्रशिक्षित अधिवक्ता है और वे पहली ऐसी मुख्यमंत्री बन गई हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले पर खुद बहस की। इसके लिए उन्होंने अदालत में एक अंतरिम आवेदन दायर कर अनुमति मांगी थी।

ममता लंबे समय से राज्य में एसआईआर अभियान का विरोध करती रही हैं और चाहती हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएं।

उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि असम में, जो एक भाजपा-शासित राज्य है, एसआईआर प्रक्रिया क्यों नहीं कराई गई।

पश्चिम बंगाल में एसआईआर 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी और मसौदा मतदाता सूची 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 19 जनवरी थी। अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित होने की उम्मीद है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की प्रगति को देखते हुए समय सीमा बढ़ाई जा सकती है।

उनके वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने एसआईआर प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अनमैप्ड मतदाताओं का हवाला दिया और कहा कि सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बहुत कम समय बचा है।

बार एण्ड बैंच ने दीवान के हवाले से कहा, अनमैप्ड मतदाता 32 लाख हैं। तार्किक विसंगति सूची में 1.36 करोड़ नाम हैं और 63 लाख मामलों की सुनवाई लंबित है।''

सुप्रीम कोर्ट की बैंच ने दो याचिकाओं में नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शरद पवार ने सुनेत्रा से मुलाकात की

बारामती (महाराष्ट्र), 04 फरवरी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को परिवार के मुखिया के रूप में नरम रुख दिखाया। एनसीपी के दोनों गुटों के विलय के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले अभी एक-दूसरे का साथ देना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कुछ दिन पहले उन्होंने रास्ता बंद (रोड ब्लॉक) वाला बयान दिया था।

- इससे पहले उन्होंने अजित पवार के बेटों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की थी।

शरद पवार ने दिवंगत अजित पवार के बेटों से बंद कमरे में मुलाकात की। इसके बाद वह बारामती में सुनेत्रा पवार के घर गए तथा अजित पवार को श्रद्धांजलि दी।

वरिष्ठ नेता शरद पवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)